95/c

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT,
1-CANNING LANE, K. G. MARG, NEW DELHI.

F.No.60(313)/DWCD/WEC/COI/2015/11184-200 Dated: 19 JAN 2016

NOTIFICATION

Whereas, Delhi Legislative Assembly vide Resolution passed on 03.08.2015 under Rule 90 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi resolved that a Commission of Inquiry be constituted by the Government of National Capital Territory of Delhi in pursuance to section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) to receive complaints regarding crimes such as violence, sexual harassment, stalking, voyeurism etc. committed against women since February, 2013 and to suggest action to the Government of National Capital Territory of Delhi and to address any other issue which Commission may find relevant during the course of inquiry into the complaints committed against women.

Whereas, the Government of National Capital Territory Delhi in pursuance of the resolution of Delhi Legislative Assembly has decided to constitute an Independent Commission of Inquiry under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) for inquiring complaints of crime committed against women since February, 2013.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section-3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952, (60 of 1952) the Government of National Capital Territory of Delhi hereby appoints the Commission of Inquiry on Women Safety consisting of the following persons with effect from the date of notification, namely:-

1. Sh. Dinesh Dayal, Retired Distt. Judge, — Chairman
2. Ms. Richa Pandey Mishra — Member
3. Dr. Surbhi Singh — Member

The terms of reference of the Commission shall be as under –

1. To receive unheeded complaints regarding crimes such as violence, sexual harassment, stalking, voyeurism etc., that are committed against women since February, 2013, i.e. subsequent to amendments made to IPC(1860) and CrPC (1973) on the basis of some of the recommendations made by Justice Verma Committee and to suggest action to Government of National Capital Territory of Delhi,
2. To suggest necessary amendments to the relevant laws, if any,
3. To recommend to Government of National Capital Territory of Delhi whether any case of negligence or collusion is made out prime facie in the cases examined,

4. To recommend measures to expedite all the proceedings in such criminal cases,
5. To propose measures to be taken to properly implement the provisions of existing laws as well as the recommendations of the Justice Verma Committee so as to prevent recurrence of such incidents,
6. To recommend welfare measures for improving the working condition of the real foot soldiers in the law enforcing agencies, and
7. To address any other issue/s that the Commission may find relevant during the course of its inquiry.

Having regard to the nature of inquiry to be made by the Commission and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section-(2), sub-section-(3), sub-section-(4), sub-section-5 of the said Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) should be applicable to the Commission, and the Government of National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred under sub-section-a of section-5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 hereby directs that all provisions of the sub-section-(2), (3), (4), (5) of that section and section 5 Ashall apply to the Commission.

The tenure of the Commission shall be for the period of two years from the date of notification.

The Commission shall submit its report on every three month from the date of its first sitting.

Dy. Director (WEC)
Department of Women & Child Development

F.No.60(313)/DWCD/WEC/COI/2015 41184-200 Dated: 19 JAN 2016
Copy forwarded to:-

1. The Principal Secretary to Lt. Governor, L.G. House, Rajpur Road, Delhi.
2. Secretary to the Speaker of Vidhan Sabha, Vidhan Sabha Building, Delhi.
3. Secretary to Chief Minister, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
4. Secretary to Dy. Speaker of Vidhan Sabha, Vidhan Sabha Building, Delhi.
5. Secretary to Minister of Women & Child Development and Social Welfare GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
6. Secretary to Minister of Health & Family Welfare, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
7. Secretary to Minister of Finance, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
8. Secretary to Minister of Industries, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, Delhi
9. Secretary to Minister of Education, Training & Tech. Education, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, Delhi.

94/C

10. Secretary to Minister of Food & Civil Supplies, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi
11. Secretary to Law, Justice and Legislative Affairs, GNCTD, Delhi Secretariat, I. P. Estate, New Delhi.
12. Secretary, Department of Women and Child Development, GNCTD, Delhi Gate Delhi.
13. OSD to Chief Secretary of Delhi, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
14. Dy. Secretary to Govt. of India, M/o Women & Child Development, Jeevan Deep Building, New Delhi.
15. Chairperson, Commission of Inquiry, 9, Upper Bela Road, Civil Lines, Delhi.
16. Members, Commission of Inquiry, through Chairperson, Commission of Inquiry.
17. Dy. Secretary, G.A.D. Delhi Secretariat, Delhi for publication in Part IV of Delhi Gazette Extraordinary.

Dy. Director (WEC)
Department of Women & Child Development

98/c

(दिल्ली राजपत्र भाग-चार असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
1-केनिगं लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001

सं०फा० 60(313)/डीडब्ल्यूसीडी/डब्ल्यूईसी/सीओआई/2015/41184-207 दिनांकः 19 JAN 2016

<u>अधिसूचना</u>

जबकि, दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के व्यवसाय की प्रक्रिया एवं संचालन नियमावली के नियम 90 के अंतर्गत दिनांक 03.8.2015 को संकल्प पारित किया था कि फरवरी, 2013 से महिलाओं के विरूद्ध किए गए अपराधों जैसे- हिंसा, यौन शोषण, पीछा करना, घूरना इत्यादि के लिए शिकायतें प्राप्त करने हेतु जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 की संख्या 60) की धारा 3 के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जांच आयोग गठित किया गया ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कार्रवाई हेतु सुझाव दिए जा सकें और महिलओं के विरूद्ध की गई शिकायतों में जांच के दौरान पाए गए संबंधित तथ्यों को उजागर किया जा सकें।

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा के संकल्प के अनुपालन में फरवरी, 2013 से महिलाओं के विरूद्ध किए गए अपराधों की शिकायतों की जांच के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 की संख्या 60) के अंतर्गत स्वतंत्र जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया है।

अतः जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 की संख्या 60) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा महिला सुरक्षा पर जांच आयोग नियुक्त करता है जिसमें नामतः निम्न व्यक्ति सम्मिलित होंगे जो अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगाः -

1.	श्री दिनेश दयाल, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश	अध्यक्ष
2.	सुश्री रिचा पाण्डेय मिश्रा	सदस्य
3.	डॉ0 सुरभि सिंह	सदस्य

आयोग के विचारणीय विषय निम्न प्रकार होंगे-

1. अपराध जैसे- हिंसा, यौन शोषण, पीछा करना, घूरना इत्यादि के संबंध में शिकायतें प्राप्त करना जोकि फरवरी, 2013 के बाद महिलाओं के विरूद्ध किए गए अर्थात् न्यायाधीश वर्मा समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशों के आधार पर आईपीसी (1860) और सीआरपीसी (1973) में किए गए अनुवर्ती संशोधन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कार्रवाई हेतु सुझाव देना;
2. संबंधित कानून में आवश्यक संशोधन का सुझाव, यदि कोई हो;
3. मामले की जांच के दौरान प्रथम दृष्टया में कोई मामला लापरवाही या दुरभिसंधि का प्रतीत हो तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सिफारिश;
4. ऐसे अपराधिक मामलों में सभी तरह की कार्यवाही में तेजी लाने के उपायों की सिफारिश;

5. न्यायाधीश वर्मा समिति की सिफारिशों के साथ-साथ वर्तमान कानून के प्रावधानों को उचित प्रकार लागू करने के उपाय का प्रस्ताव करना ताकि ऐसी घटनाएं दुबारा न हो;
6. कानून लागू करने वाली एजेंसी में जरूरतमंदों की वर्किंग कंडीशन के सुधार हेतु कल्याणकारी उपायों की सिफारिश; तथा
7. कोई अन्य मुद्दा प्रस्तुत करना जो आयोग जांच के दौरान उचित पाता है।

आयोग तथा मामले की अन्य परिस्थितियों द्वारा की गई जांच की प्रकृति के संबंध में उक्त जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 की संख्या 60) की धारा-5 की उपधारा-2, उपधारा-3, उपधारा-4, उपधारा-5 के सभी प्रावधान तथा उपधारा-5क आयोग पर लागू होंगे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 की संख्या 60) की धारा -5 की उपधारा-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इस धारा की उपधारा-2, 3, 4, 5 एवं 5क के सभी प्रावधान आयोग पर लागू होंगे।

आयोग का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से 2 वर्ष तक होगा।

आयोग अपनी प्रथम बैठक की तिथि से नियमित आधार पर प्रत्येक तीन माह पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

Agarwal

उप निदेशक
महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ
महिला एवं बाल विकास विभाग

सं०फा० 60(313)/डीडब्ल्यूसीडी/डब्ल्यूईसी/सीओआई/2015/ 41184-200 **दिनांक:** 19 JAN 2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः-

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राजपुर रोड़, दिल्ली।
2. सचिव, अध्यक्ष विधानसभा, विधानसभा बिल्डिंग, दिल्ली।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, दूसरा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी०एस्टेट, नई दिल्ली।
4. सचिव, उपाध्यक्ष दिल्ली विधानसभा, विधानसभा बिल्डिंग, दिल्ली।
5. सचिव, समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली।
6. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली।
7. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली।
8. सचिव, उद्योग मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली।

9. सचिव, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
10. सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
11. सचिव, विधि,न्याय एवं विधायी कार्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
12. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,जीएलएनएस कॉम्पलैक्स दिल्ली गेट, दिल्ली।
13. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
14. उप-सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, नई दिल्ली।
15. अध्यक्ष, जांच आयोग, 9 अपर बेला रोड़, सिविल लाईन, दिल्ली।
16. सदस्य, जांच आयोग को अध्यक्ष जांच आयोग के माध्यम से।
17. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सचिवालय अंग्रेजी एवं हिन्दी की प्रतियां) को दिल्ली राजपत्र भाग-चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।

उप निदेशक
महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ
महिला एवं बाल विकास विभाग

DIR. WCD
Diary No. 2314
Dated 7/8/15

Office of the Secretary(SW/WCD)
Deptt. of Social Welfare
Govt. of NCT of Delhi
6 AUG 2015
Dy. No. 493/V18

सत्यमेव जयते

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
Delhi Legislative Assembly Secretariat

No F. 22(1)/R-90/2015/LAS-VI/Leg./ 4184 Dated: 4-8-15

To,
The Principal Secretary (Women & Child Welfare)
Govt. of NCT of Delhi,
Delhi

PA
Call Dir (WCD) to discuss urgently.

Subject: Resolution under Rule 90 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

Sir,

The following Resolution under Rule 90 moved by Sh. Sandeep Kumar, Hon'ble Minister of Women & Child, Social Welfare, and SC & ST was adopted by the House on 3rd August, 2015:

PA → DWCD
Pl. ex. & urgently
6.8.15

"That having noted with anguish and deep sense of regret the ever increasing incidence of crime against women in the National Capital Territory of Delhi and perceived negligence and inability on the part of law enforcing agency in dealing with this grave situation, this House resolves that:

Pursuant to Section 3 of *The Commission of Inquiry Act, 1952,* a Commission of Inquiry, consisting of not more than three members including a retired Judge who will be its Chairman, be constituted by the Government of National Capital Territory of Delhi.

The House further resolves that:

The terms of reference for the Commission so constituted shall, broadly, be:

1. **To receive unheeded complaints regarding crimes such as violence, sexual harassment, stalking, voyeurism etc., that are committed against women since February, 2013, i.e.**

पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054 Old Secretariat, Delhi - 110054
दूरभाष / Tel : 23890468, 23890109, 23890007 फैक्स / Fax : 011-23890128, 011-23890468

subsequent to amendments made to IPC and CrPC on the basis of some of the recommendations made by Justice Verma Committee and suggest action to Government of National Capital Territory of Delhi,

2. To suggest necessary amendments to the relevant laws, if any,
3. To recommend to Government of National Capital Territory of Delhi whether any case of negligence or collusion is made out prime facie in the cases examined,
4. To recommend measures to expedite all the proceedings in such criminal cases,
5. To propose measures to be taken to properly implement the provisions of existing laws as well as the recommendations of the Justice Verma Committee and to prevent recurrence of such incidents,
6. To recommend welfare measures for improving the working condition of the real foot soldiers in the law enforcing agencies, and
7. To address any other issue/s that the Commission may find relevant during the course of its inquiry.

The House also resolves that:

The Government of National Capital Territory of Delhi is wholly authorized to enlarge the scope of inquiry to be conducted by the Commission thus constituted, if the circumstances so warrant."

The text of the Resolution is being forwarded for further necessary action, as mandated under section 3 of the Commission of Inquiry Act 1952.

Further, under Rule 106 (2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business, the Hon'ble Minister has to inform the status of the Resolution in the next session. The Hon'ble Minister may be accordingly informed please.

Yours faithfully,

(C. Velmurugan)
Deputy Secretary (Legislation)

Encl : As above.